at Guntur Railway Station on Arundelpet side, to facilitate the movement of commuters there; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Promotions in Central Public Wroks Department

1827. SHRI RAM AWADESH SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the sealed cover procedure in CPWD is followed for Group 'B' and 'C' staff;

(b) whether it is a fact that for group 'A' the said procedure is not applicable;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) if not, the reasons for which group 'A' officer whose vigilance cases are pending have been promoted; and

(e) the details of the policy being follwed by CPWD authority in this regard to promotion?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. It is applicable.

(c) In view of reply to part (b), the question does not arise.

(d) and (e) Cases of officers against whom disciplinary proceedings are pending are considered for *ad hoc* promotion keeping in view the orders of the Department of Personnel and Training and with the approval of the appointing authority.

शहरी मूलभूत सुख-सुविधा योजना

1828. **श्री शिव प्रताप मिश्र** : क्या शहरी **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ की गई शहरी मूल-भूत सुख-सुविधा योजना के अधीन मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले को सहायता प्रदान की गई है जबकि अन्य जिलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का लाभ अन्य स्थानों के व्यक्तियों को भी देने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त योजना के अधीन अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत इन्दौर जिला तथा इस जिले के इन्दौर, महु, दिपालपुर, सनवर तथा मधुगांव कस्बों को क्रियान्वयन के लिए चुना है ।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान राज्य सरकार से शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत किसी भी अन्य कस्बों को शामिल नहीं किया था क्योंकि योजना का कार्यान्वयन केवल प्रायोगिक स्तर पर किया जा रहा था । यद्यपि 1990-91 के दौरान योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है तथा राज्य सरकारों से प्रस्ताव तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(घ) योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय की गयी राशि और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 154 अनुपत्र सं० 87]

मध्य प्रदेश के लिए, "हुडको" द्वारा दी गई सहायता

1829. **श्री अजीत जोगी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हुडको द्वारा मध्य प्रदेश के आवास बोर्डों विकास-प्राधिकरण, सुधार न्यासों और सहकारी आवास समितियों को कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) इससे किस-किस श्रेणी के कितने-कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1989–90 के दौरान मध्य प्रदेश में हुडको ने आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, सहकारिता आदि को 56.29 करोड़ रुपये की ऋणराशि से, दो शहरी अधसंरचनात्मक परियोजनाओं सहित 102 योजनायें स्वीकृत की हैं। यह योजनायें मकानों के निर्माण, प्लाटों के विकास तथा नीचे दिये गये श्रेणी-वार ब्यौरों के अनुसार रिहायशी कालोनियों के लिये स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को बढ़ावा देगी :—

श्रेणी	निर्मित किये जाने वाले मकानों की संख्या	विकसित किये जाने वाले प्लाटों की संख्या	आंनसाइट योजना (लाभ-भोगी)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	175110	9050	5940
निम्न आय वर्ग	2835	990	2740
मध्यम आय वर्ग	2570	626	8980
उच्च आय वर्ग	472	—	16280

इसके अतिरिक्त हुडको ने मध्य प्रदेश में 5 78 करोड़ रुपये की ऋण, राशि से 82113 आधारभूत स्वच्छता प्रबन्ध इकाइयां स्वीकृत की हैं।

Increase in the quantum of essential commodities being supplied through PDS

1830. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the 'Public Distribution System' per unit allocation of rice, wheat and sugar is very low and each consumer is allotted only 0·50 kg of rice and 0·60 kg of wheat in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether Government propose to increase per capita allotment of these essential commodities through the Public Distribution System ; and

(c) whether it is also a fact that sugar allocation to various states is made on the basis of projected population of 1986 and if so, whether Government propose to make allocation of sugar on the basis of projected population of 1989 ?